प्रेषक,

एम०एच० खान, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

1— मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून / हरिद्वार / हल्द्वानी—काठगोदाम।

2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 2/ फरवरी, 2013

विषय: नगर निकायों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में। महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 232/IV(2)/2013-श0वि0-12(सा)10, दिनांक 20.02.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानीय नगर निकायों को नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1916 में निर्धारित प्रक्रियानुसार कर निर्धारण एवं कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2— उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि नगर निकायों हेतु कर प्रणाली में सुधार हेतु नियमावली एवं बोर्ड का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः जनिहत में अग्रिम आदेशों तक राज्य के नगर निगमों द्वारा अधिसूचना संख्याः 1435/9.9.2000—63ज/95टी०सी०, दिनांक 22.04.2000 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही नहीं की जायेगी, अपितु पूर्व से ही नगर निगमों में प्रचलित व्यवस्था/प्राविधानों के अनुरूप कर का निर्धारण एवं वसूली की जायेगी।

भवदीय,

(एम०एच० खान) सचिव।

संख्याः 294/IV(2)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के शासनादेशों में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

5- गार्ड फाईल।